POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2016/अंक 07

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जुलाई, 2016 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! दो साल पूरे कर लिए हैं मोदी सरकार ने। सरकार की कामयाबियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भरोसा जताया है कि वह देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को खास अहमियत देगी। इसके लिए व्यापक रणनीति और सुधारों की प्रक्रिया तय की गई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज गति मिलेगी।

फिलहाल, सरकार ने इन दो सालों में देश की आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जिनके परिणाम भी सुखद रहे हैं। जन-धन योजना के तहत करीब 22 करोड़ गरीब परिवारों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना व उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन जैसी कई योजनाएं सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में अहम साबित हुई हैं।

मनरेगा योजना के अलावा किसानों के हित में फसल बीमा, मृदा हैल्थ कार्ड, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा नई कृषि ऋण व्यवस्था जैसे कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं। नवयुवकों के लिए रोजगार जुटाने में मुद्रा बैंक, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाएं नए अवसर पैदा कर उन्हें लाभान्वित करेंगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि व किसानों का कल्याण है। किसान कर्जे में डूबा है। उसकी आय नहीं बढ़ रही, किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति में इजाफा आवश्यक है। मद्देनजर बजट में किसानों की आय को दोगुना करने की घोषणा के त्वरित क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

पानी के दुरुपयोग को रोकने का कानून में होगा प्रावधान

पानी की चोरी पर लगेगी रोक

फिलहाल पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का विभाग के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, सिर्फ कनेक्शन काटने का सीमित अधिकार है। पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। खेती के लिए भी बूंद-बूंद सिंचाई का फॉर्मूला काम में लेना होगा। इसके लिए काश्तकारों को बाध्य किया जा सकेगा।

प्रदेश में पानी के दुरुपयोग को रोकने और जरूरतमंद को पेयजल मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार राजस्थान वाटर एक्ट ला रही है। विभाग की ओर से इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस पर केबिनेट की मुहर लगेगी।

दरअसल, प्रदेश में पानी को लेकर किसी तरह का कोई कानून नहीं है। महज गाइडलाइन के जरिए ही पानी के उपयोग और दुरुपयोग को लेकर विभाग कार्य करता है। करीब आठ माह पहले विभागीय स्तर पर एक कमेटी बनी थी। कमेटी द्वारा विभिन्न राज्यों के वाटर एक्ट का अध्ययन कर राज्य के लिए वाटर एक्ट का मसौदा तैयार किया गया।

इसमें मोटे तौर पर पानी के दुरुपयोग को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही डार्क जोन में अति जलदोहन करने वालों पर भी शिकंजा कसने के नियम बनाए गए हैं। नियमों में जुर्माने से लेकर सजा तक का प्रावधान है।

भारी पड़ा बिस्किट के पैकेट का वजन कम होना

नागौर निवासी नन्दकिशोर तिवाड़ी ने 10 अक्टूबर 2014 को ब्रिटानिया बिस्किट का 400 ग्राम का पैकेट खरीदा था। इसका वजन 313 ग्राम ही निकला। इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच नागौर में परिवाद दर्ज कराया। मामले की सुनवाई पर मंच ने ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि. को दोषी माना और तिवाड़ी को 20 हजार रुपए मानसिक व्यथा और 15 हजार रुपए परिवाद खर्च के अदा करने के आदेश दिए। साथ ही पैकेट की कीमत और एक माह में राशि का भुगतान नहीं करने पर उस पर ब्याज देने के आदेश भी दिए।

ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज ने जिला मंच के फैसले के खिलाफ राज्य आयोग में अपील की। आयोग में सुनवाई पर ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज ने दलील दी कि मूल बिस्किट का पैकेट और बिल जिला मंच में पेश नहीं हुआ। जबकि आयोग ने पाया कि जिला मंच में बिस्किट का पैकेट पेश हुआ था, जिसका वजन 87 ग्राम कम पाया गया। मूल बिल नहीं होने की दलील को नकारते हुए आयोग ने कहा कि विवाद पैकेट के वजन का है न कि मूल बिल का। अपील महज उपभोक्ता को परेशान करने के लिए दर्ज की गई है। आयोग ने अपील को खारिज करते हुए ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि. को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता नन्दकिशोर तिवाड़ी को परिवाद खर्च सहित 40 हजार रुपए अदा करे।

आवश्यक है वित्तीय उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण

अमूमन यह देखा गया है कि आज भी आम उपभोक्ता अपने वित्तीय अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है और न ही उन्हें बैंकिंग नियमों की सही जानकारी होती है। उन्हें वित्तीय व्यवहार करते समय किसी भी पेपर पर बिना पढ़े और समझे हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी 'कट्स' द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक सहयोग से जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम के शुभारम्भ के अवसर पर जयपुर में आयोजित कार्यशाला में श्रीमती माधवी शर्मा, बैंकिंग लोकपाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्यअतिथि के रूप में उक्त जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारियों को भी वित्तीय व्यवहार करते समय ग्राहकों को उसके फायदे और जोखिम के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

कार्यशाला में जॉर्ज चेरियन, निदेशक, 'कट्स' ने अपने प्रारम्भिक उद्बोधन में कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संसद में 2013 में दी गई जानकारी के अनुसार विभिन्न बैंकों में बिना दावों के खातों में जमा कुल राशि 3652 करोड़ रुपए है। इन खातों में 10 सालों से कोई लेन-देन नहीं हो रहा। उपभोक्ताओं को वित्तीय अधिकारों के प्रति जागरूक करने का यह कार्यक्रम संचालित करने के लिए 'कट्स' राजस्थान की पहली संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत हुई है।

कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में विभिन्न बैंको के विषय विशेषज्ञों ने बैंकिंग व्यवहार से संबंधित कई जानकारियां देकर प्रतिभागियों को लाभान्वित किया।

देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा!

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनका एक सूत्री एजेंडा भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। वह कभी भी देश को गलत रास्ते पर लेकर नहीं जाएंगे। उन्होंने राजग सरकार के दो वर्ष पूरे होने के जश्न पर एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के सत्ता में आने के दो सालों के भीतर जनता ने बदलाव देखा है। लोगों को भरोसा है कि यह सरकार देश को आगे लेकर जा सकती है।

सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया है। अगर किसानों की जरूरतों को पूरा किया गया तो उनकी धरती सोना उगलेगी।

आदर्श गांव चुनने की रफ्तार धीमी

ऐसा लगता है कि इस बार भी प्रदेश में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत आदर्श गांव चुनने में विधायक रुचि नहीं ले रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष में विभाग के मांगने पर भी ज्यादातर विधायकों ने अभी तक गांव के नाम तक नहीं सुझाए हैं।

पिछली बार भी विधायकों की धीमी रफ्तार के चलते चुने गए कई गांवों में अभी तक विकास के स्वीकृत कार्य पूरे होने की बाट जोह रहे हैं। आधे से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में तो विधायक साल के खत्म होने तक केवल आदर्श ग्राम का नाम ही सुझाते रहे थे। इसके बाद भी बजट जारी करने में हुई देरी से आदर्श गांव विकास से महरूम रहे और अभी तक बदहाली का शिकार हैं। विधायकों की रुचि नहीं होने से एक अच्छी योजना को पंख नहीं लग पा रहे हैं।

बीपीएल को मुफ्त बिजली कनेक्शन

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शन की आस लगाए बैठे हजारों परिवारों के लिए अच्छी खबर है। बिजली कंपनियां ऐसे गांवों में जरूरतमंदों को बिजली कनेक्शन देने के लिए विशेष शिविर लगा रही है। यह हर माह के पहले और तीसरे रविवार को लगाया जाएगा।

शिविर में ग्रामीण उपभोक्ताओं को मौके पर ही कनेक्शन जारी होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन भी दिए जाएंगे। इस साल आठ लाख घरेलू परिवारों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों को मिलेगा अनुदानित ऋण

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने सहकार किसान कल्याण योजना को विस्तारित करने की घोषणा की है। अब किसानों को सहकारी बैंकों से अधिक गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा मिलेगी। इससे गांवों में आय के साधन विकसित होंगे।

योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का अनुदानित ऋण दिया जाएगा। किसानों को फार्म यंत्रीकरण, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, वाहन खरीद सहित विविध उद्देश्यों के लिए ऋण दिया जाएगा। इस ऋण पर राज्य सरकार द्वारा दो फीसदी ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

बिजली चोरी में नेता भी शामिल

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बिजली चोरी करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि लाइनमेन से लेकर अधिकारी तक को रिश्वत दी जाती है। ऐसे में हो सकता है इस खेल में उद्योग के साथ नेता भी शामिल हों।

गोवा में बिजली मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि गरीब लोग बिजली चोरी में शामिल नहीं हैं। किसान भी ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि उसे पहले से ही सस्ती बिजली मिलती है। डिस्कॉम चेयरमैन श्रीमत पांडे ने अधिकारियों को आगाह किया है कि बिजली चोरी मामले में यदि अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आती है तो उन्हें नहीं बक्शा जाएगा।

इस ग्राम पंचायत में सिर्फ भ्रष्टाचार

बांसवाड़ा जिले की चिकली ग्राम पंचायत। यहां कागजों में करोड़ों रुपए के काम हुए हैं लेकिन जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इनका भौतिक सत्यापन किया तो भ्रष्टाचार के

अलावा कुछ नहीं मिला। इस पंचायत में 53 योजनाओं में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। हैंडपंप लगवाने से लेकर सड़क और पुलिस के कामों में घोर अनियमितता मिली।

काम हुए बिना ही करोड़ों रुपए का भुगतान उठा लिया गया। इस पंचायत की जांच में ब्यूरो अधिकारियों को ढ़ाई महीने लग गए। अब सरपंच, पूर्व सरपंच, सचिव, एईएन, जेईएन सहित आठ पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

विकास कागजों में दर्ज

ग्राम गदर मई का अंक पढ़ा। इसमें प्रश्न उठाया गया कि विकास अभियानों के परिणाम जमीन पर नजर क्यों नहीं आते? इसके पीछे का रहस्य यह है कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र गिर गया है। ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता से कार्य करने की भावना खत्म होती जा रही है। अच्छा वेतन पाने वाले भी रिश्वत ले रहे हैं, शर्म उन्हें नहीं आती। विकास होता नहीं बिल पास जरूर हो जाते हैं। विकास कागजों में दर्ज होता रहता है और वह जमीन पर उतरता ही नहीं। फिर दिखेगा कैसे?

समय आ गया है नरेन्द्र मोदी देशवासियों को अब चरित्र निर्माण व ईमानदारी की सीख दें। इस बारे में सभी सांसद व विधायक शपथ-पत्र दाखिल करें तो पांच साला योजना तीन साल में ही पूरी होती नजर आएगी। देखना यह है, मोदी सरकार कैसे कदम उठाती है।

- घेवर चन्द गोदिका, जयपुर

बनेगी जैविक कृषि नीति

केन्द्र की मोदी सरकार ने एक अप्रेल से किसानों को जैविक खेती के लिए बीस हजार रुपए प्रति हैक्टेयर अनुदान दिए जाने की घोषणा की है। इसके बाद प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 'जैविक कृषि नीति' बनाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति अन्य राज्यों में बनाई गई जैविक कृषि नीति का अध्ययन कर रही है।

प्रदेश में अभी करीब चालीस हजार हैक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है। इस पर राज्य सरकार आठ हजार प्रति हैक्टेयर का अनुदान दे रही है। समिति कुछ क्षेत्र और फसलों का भी चयन कर रही है, ताकि सरकार और किसान का इस तरफ ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

गांव-ढाणियों में पेयजल मुहैया नहीं

प्रदेश के रेगिस्तानी और सूखे ग्रामीण इलाकों की हजारों ढाणियों में लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 1163 गांव-ढाणियों में पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से राज्य सरकार को केवल 563 ढाणियों में ही पेयजल पहुंचाने में सफलता मिल पाई है।

यह आंकड़े खुद राज्य सरकार ने पेश किए हैं। इसका खुलासा राष्ट्रीय पेयजल योजना में राज्य की वार्षिककार्य योजना को लेकर केन्द्र में आयोजित बैठक में हुआ है। राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना में केन्द्र सरकार से करीब 50 हजार करोड़ रुपए मिले, तब ही शेष गांव-ढाणियों में पेयजल मुहैया हो सकता है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर